भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1495

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

भारी उद्योगों की स्थापना

1495. श्रीमती अनुप्रिया पटेल:
श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री बी. वी. नाईक:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नए भारी उद्योगों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में नए उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) और (ख): उद्योग राज्य का विषय है। भारी उद्योग विभाग की भूमिका अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक सीमित है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम वाणिज्यिक आधार पर अपने एककों की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं।

(ग) और (घ): इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

******